एक नजर

बातचीत ही मणिपुर में शांति बहाल करने का एकमात्र रास्ता- रिजिजू

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि बातचीत ही जातीय हिंसाग्रस्त मणिपुर में शांति बहाल करने का एकमात्र तरीका है और राज्य में हालात को सामान्य बनाने का प्रयास करना नरेन्द्र मोदी सरकार का अगला कदम होगा। रिजिजू ने पूर्वोत्तर राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी जातीय संघर्ष के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। मणिपुर में हिंसा के दौरान कम से कम 219 लोगों की मौत हो चुकी है। रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में समस्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र के खिलाफ विद्रोह नहीं बल्कि दो प्रमुख समुदायों मैतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा-अगर कोई भी मणिपुर में शांति बहाल करने में मदद करना चाहता है तो पहले जाकर मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से अपील करें कि वे हथियार न उठाएं। सशस्त्र संघर्ष से कोई समाधान नहीं निकलेगा। शांति बहाल करने और हालात को सामान्य बनाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत ही एकमात्र समाधान है। मणिपुर में विकास बहाल करना हमारा अगला प्रयास होगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा कि सरकार शांति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर के साथ-साथ संसद से भी शांति बहाल करने की अपील की थी। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले रिजिजू ने कहा कि जो लोग मणिपुर में शांति चाहते हैं, उन्हें दृढ़ता से कहना चाहिए कि संघर्षरत समूहों को हिंसा रोकनी चाहिए और एक-दूसरे से बात करनी चाहिए क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा-केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) वहां (मणिपुर) चार दिन रहे, हमारे गृह राज्य मंत्री (नित्यानंद राय) 22 दिन तक वहां रहे और कई अधिकारी वहां थे। रिजिजू ने राज्य में दो समुदायों के बीच जारी जातीय संघर्ष के लिए उच्च न्यायालय के उस आदेश को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा कि संघर्ष उस समय शुरू हुआ, जब उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर मैतेई को एसटी का दर्जा देने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा-क्या आपको नहीं लगता कि उच्च न्यायालय का यह अपने आप में एक अनोखा आदेश था? किसी समुदाय का आदिवासी या गैर-आदिवासी के रूप में निर्धारण करना सरकार का काम है। यह एक नीतिगत मामला है। उन्होंने कहा-जब उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि एक पक्ष को तीन महीने के भीतर एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए तो स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया हुई। इसलिए झड़पें हुईं। अगर कोई कहता है कि मणिपुर में झड़प की वजह केंद्र है तो उसे इस तरह की टिप्पणी करने के लिए मूर्ख या सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कहा जाना चाहिए।

लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र का एक प्रारूप मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस मेनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों ने सौंपा

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में श्रमिकों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवर, केंद्र सरकार के कम से कम 30 लाख रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया है, जिसका एक मसौदा पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस मेनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों द्वारा सौंपा गया था। सूत्रों के मुताबिक, घोषणापत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने, अखिल भारतीय जाति जनगणना और ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर, जिसे अधिकार-आधारित कानून के रूप में पेश किया जा सकता है, में संभवत: पेंशन,

विकलांगता और जीवन बीमा शामिल होगा। यह योजना उस कानून पर आधारित है जिसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल राज्य में लागू किया था। पार्टी न्यूनतम आय योजना (एनवाईएवाई) कार्यक्रम को भी दोबारा शुरू कर सकती है और देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों में सबसे बुजुर्ग महिला को सालाना रुपये 72,000 की पेशकश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घोषणापत्र में सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को खत्म करने का भी वादा किया जा सकता है। इसमें एमएसपी कानून, जाति जनगणना, बेराजगारी और महंगाई पर भी फोकस रह सकता है।

घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने पैनल के सदस्यों के साथ बुधवार को खड़गे को घोषणापत्र का मसौदा सौंपा। घोषणापत्र को अंतिम रूप देने के लिए अब पार्टी की कार्य समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव संयोजक हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, जयराम रमेश, शशि थरूर और प्रियंका गांधी वाड्रा पैनल के अन्य सदस्य हैं। कुल मिलाकर, घोषणापत्र राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा (बीजेएनवाई) के प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होने की संभावना है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर जोर देते हुए संविधान की रक्षा पर केंद्रित है।

केंद्रीय एजेंसियां दिल्ली में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के मकानों को गिराने का कर रही प्रयास: आप

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के अधीन एजेंसियां उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के मकानों को ढहाने की कोशिश कर रही हैं।

स्थानीय लोगों ने बुधवार को दावा किया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यमुना बाढ़ क्षेत्र में गुरुद्वारा मजनू का टीला के पास रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को जगह खाली करने का नोटिस जारी किया है। डीडीए के एक अधिकारी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश

के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान शुरू करने की पुष्टि की। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण अभियान स्थगित कर दिया गया। भारद्वाज ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया-डीडीए ने पिछले 13 वर्षों से मजनू का टीला इलाके में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नोटिस जारी कर उन्हें अपना सामान बांधने और जगह छोड़ने को कहा है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एनजीटी ने नवंबर 2019 में मजनू का टीला गुरुद्वारे के पास झुग्गीवासियों द्वारा यमुना बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए डीडीए और दिल्ली सरकार को अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया था। निकाय ने इस साल 29 जनवरी को एक आदेश के जरिए डीडीए पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को न्यायालय का समन, 16 मार्च को होना होगा पेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। शराब घोटाला से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि ईडी के 8 समन के बाद भी दिल्ली के सीएम जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी ने दोबारा कोर्ट का रुख किया था।

हालांकि, ईडी पहले भी कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत कर चुकी है। दरअसल, पांचवें समन के बाद ईडी ने शिकायत की थी, जिस पर सात फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 17 फरवरी को कोर्ट में

पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, अरविंद केजरीवाल के वकील ने बजट सत्र के चलते अगली तारीख पर पेश होने की दलील देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के आठवें समन का जवाब देते हुए कहा था कि ईडी का समन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी। इसके साथ उन्होंने कहा था कि वह एजेंसी के सवालों का जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे। वहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोर्ट इस संबंध में आदेश देगी, तभी वो प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 17 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी और 27 फरवरी को समन भेजे थे। मगर वो एक बार भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। इस दौरान ईडी ने दो बार कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत की।

भारत ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में दक्षिण एशिया की बढ़ाई हिस्सेदारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत और लचीली हो गई है, आर्थिक विकास तिमाही दर तिमाही मजबूत हो रहा है, तीसरी तिमाही की 8.4 प्रतिशत की वृद्धि आने वाली तिमाहियों में भी मजबूत विकास पथ जारी रहने का संकेत देती है। हाल की तिमाहियों में विनिर्माण, निर्माण और बिजली क्षेत्र प्रमुख विकास चालक बन गए हैं। एनएसओ (राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत) द्वारा 2023-24 में 7.6 प्रतिशत की अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि न केवल अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में बल्कि कई उभरते और विकासशील देशों में भी सबसे अधिक है।

आईएमएफ के हालिया अपडेट (जनवरी 2024) के अनुसार, 2024 में विश्व अर्थव्यवस्था 3.1 प्रतिशत, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं 1.5 प्रतिशत और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेंगी। भारत दक्षिण एशिया की वृद्धि का महत्वपूर्ण समर्थन कर रहा है, जिसके 2024 में 5.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक जीडीपी में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी 2014 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 4.5 प्रतिशत हो गई है। वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 3.4 प्रतिशत हो गई है। दक्षिण एशिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 77 प्रतिशत से बढ़ गई है। इसके बाद दक्षिण एशिया सकल घरेलू उत्पाद में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 2014 में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में लगभग 10 प्रतिशत हो गई। हाल के वर्षों में भारत ने साल दर साल बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विशेषता वाले प्रगतिशील विकास पथ का अनुभव किया है। कृषि, विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, खनन और उत्खनन, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं सहित सभी आर्थिक बुनियादी सिद्धांत भारत की समग्र वृद्धि और विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार के रणनीतिक सुधारों और विवेकपूर्ण नीतिगत उपायों और उद्योग के प्रयासों के दम पर विनिर्माण क्षेत्र 2023-24 की तीसरी तिमाही में 11.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। व्यापार करने में महत्वपूर्ण आसानी के साथ-साथ कठिन अनुपालनों को हटाने और कई छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार किया है। हाल ही में व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने के लिए 40,000 से अधिक अनुपालन हटा दिए गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध से मुक्त कर दिया गया है। नई प्रौद्योगिकियों और मजबूत इको-सिस्टम के आगमन के साथ देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बन गया है। 2023-24 की तीसरी तिमाही में सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल घरेलू उत्पाद का 32.4 प्रतिशत रहा, जो 2022-23 की तीसरी तिमाही के 31.8 प्रतिशत से अधिक है, जो देश में स्थिर क्षमता विस्तार और समग्र मांग के मजबूत होने और आने वाले समय में अधिक रोजगार के अवसरों का संकेत दे रहा है।

वैश्विक महामारी के बाद और भू-राजनीतिक प्रतिकूलताओं के बीच, भारत की जीडीपी महामारी के बाद के सभी वर्षों में लगातार 7 प्रतिशत से अधिक रही है, 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत, 2022-23 में 7.2 प्रतिशत और 2023-24 में 7.6 प्रतिशत रही है। भारत वित्त वर्ष 2024-25 तक 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, वित्त वर्ष 2026-27 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2030 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हम खुद को एशिया में दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार हैं।

कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी की सूचना मिलने पर मचा हड़कंप

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कॉलेज को गुरुवार को बम से उड़ने की धमकी मिलने के बाद अफरातफरी मच गई।बता दें सूचना मिलने के तत्काल बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। छात्रों को कॉलेज से बाहर निकालने के बाद पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने कैंपस में सर्च ऑपरेशन चलाया।

आपको बता दें दिल्ली पुलिस और खोजी दस्ते द्वारा तलाशी अभियान में बाद राम लाल आनंद कॉलेज में स्थित सामान्य हो गया है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि किसने कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी छात्रों में भय का माहौल छा गया सभी इधर-उधर भगने लगे। दरअसल, दक्षिणी दिल्ली

के राम लाल आनंद कॉलेज के एक कर्मचारी के वॉट्सएप पर सुबह नौ बजकर 34 मिनट पर एक कॉल आई जिसमें कॉलेज को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। बम से उड़ाने को लेकर धमकी की सूचना मिलने के बाद कॉलेज में हड़कंप मचा गया।

छात्रों ने इसकी सूचना कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ को दी। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने अफरातफरी के बीच घर भेजा दिया गया। साथ ही पुलिस ने पूरे कॉलेज परिसर को खाली करा लिया। इसी बीच पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई जिसके बाद थाना पुलिस सहित डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दल कॉलेज में पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी हो गई और कॉलेज परिसर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

दुकान में घुसकर दवा विक्रेता और पत्नी से की मारपीट, दी तहरीर

ग्रेटर नोएडा (संवाददाता)। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख क्षेत्र में दवा विक्रेता और उसकी पत्नी से दुकान में मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र में गौड़ सिटी-2 में पटना फार्मेसी नामक दवा की दुकान है।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि दुकान पर कुछ लोग आए और दवा वापस करने को लेकर झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और आरोपियों ने दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी । इस बीच बचाव में आई दुकानदार की पत्नी के साथ भी मारपीट कर दी गई।

पीड़ित दुकानदार ने पूरी घटना की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष एक दूसरे के परिचित हैं। किसी पुराने विवाद के चलते झगड़ा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है।

युवक की चाकू मार की हत्या

नई दिल्ली (संवाददाता)। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि गौरव सिंघल नाम के 29 वर्षीय व्यक्ति को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चाकू मार दिया गया। देवली एक्सटेंशन के राजू पार्क में एक हत्या के संबंध में रात करीब 12.30 बजे टिगरी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पता चला कि पीड़ित पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। पुलिस ने बताया कि घायल को उसके परिवार के सदस्य इलाज के लिए मैक्स अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स शवगृह में भेज दिया गया है।

आगे पुलिस ने बताया कि पीड़ित की हत्या उसकी शादी से एक दिन पहले की गई थी। इस रिपोर्ट को दर्ज करने के समय संघर्ष का वास्तविक कारण अज्ञात था। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। आगे की जांच चल रही है। पुलिस के अनुसार, इससे पहले बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक 23 वर्षीय व्यक्ति के पेट में चाकू मार दिया गया था। मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई। घटना के संबंध में रात करीब 1 बजे पुलिस स्टेशन, मालवीय नगर में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से बारात आ रही है। पुलिस ने बताया कि बारात में बेगमपुर, मालवीय नगर से कुछ ढोलवालों को बुलाया गया था। पुलिस ने बताया कि नृत्य के दौरान ढोलवालों के बीच कुछ बहस हुई और उनमें से एक ने एक व्यक्ति के पेट में चाकू मार दिया। पुलिस ने बताया कि घायल को उसके रिश्तेदारों ने सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। आरोपियों की पहचान आशीष और अमित के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह भी पता चला कि घायल और आरोपी रिश्तेदार थे।

माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों पर आक्रमण के षड़यंत्रकर्ता को गृह मंत्रालय ने किया आतंकवादी घोषित

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया। वह वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में रह रहा है। मोहम्मद कासिम गुज्जर 2022 में माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों पर हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता था, जिसमें चार लोग मारे गए थे और दो दर्जन से अधिक घायल हो गए थे।

कासिम 2021 में जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक भाजपा नेता के घर पर ग्रेनेड हमले में भी शामिल था, जिसके

परिणामस्वरूप एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) स्थित लश्कर कमांडर मोहम्मद कासिम उर्फ सुलेमान मूल रूप से रियासी जिले के महोर के अंगराला गांव का निवासी है और दशकों से फरार है।

भाजपा नहीं चाहती कि चुनावी बॉण्ड खरीदने वालों के नाम उजागर हों - कांग्रेस अध्यक्ष

भोपाल (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि चुनावी बॉण्ड खरीदने वालों के नाम सामने आएं। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत मध्य प्रदेश के बदनावर में एक रैली में, उन्होंने उन नेताओं को अपने पाले में शामिल करने के लिए भाजपा पर कटाक्ष किया, जिन्हें वह अन्य दलों में रहते समय तब दागी कहती थी।उन्होंने कहा, आरबीआई भाजपा की बात सुन रहा है और उन लोगों के नाम का खुलासा नहीं कर रहा जिन्हें गुप्त रूप से चुनावी बॉण्ड जारी किए गए थे।

खरगे ने जुबान फिसलने की वजह से भारतीय स्टेट बैंक की जगह रिजर्व बैंक का नाम लिया। खरगे ने कहा कि बैंक उन लोगों के नाम का खुलासा नहीं करना चाहता जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से क्लीन चिट पाने के लिए पैसे दिए। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने 15 फरवरी के फैसले में बैंक को खरीदारों के नाम का खुलासा करने का निर्देश दिया था लेकिन

बैंक कह रहा है कि उसके पास डाटा तैयार नहीं है।

न्यायालय ने इस फैसले में राजनीतिक चंदा देने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था। खरगे ने आगे कहा, आप नाम क्यों छिपा रहे हैं?....इसका मतलब है कि इन सभी लोगों ने चोरी करके चंदा इकट्ठा किया है और वे इस लूट को जारी रखना चाहते हैं। एसबीआई ने सोमवार को शीर्ष अदालत का रुख कर राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को छह मार्च तक चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस बीच, कांग्रेस प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधा और उन पर झूठे दावे व वादे करने का आरोप लगाया।

खरगे ने कहा-भाजपा अन्य दलों के नेताओं को अपने पाले में लाती है। जब ये नेता दूसरे दलों में होते हैं, तो वह उन्हें दागी करार देती है, लेकिन जब वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो वे साफ-सुथरे हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पास एक बड़ी वॉशिंग मशीन है और ये दागी नेता इससे गुजरने के बाद साफ-सुथरे हो जाते हैं।'' उन्होंने व्यापम घोटाले और 2023 के सीधी पेशाब कांड का जिक्र करते हुए राज्य के भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने जाति आधारित जनगणना कराने की पार्टी की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

जुए-सट्टेबाजी का प्रमोशन नहीं कर पाएंगे सेलिब्रिटी, सीसीपीए ने जारी किया परामर्श

नई दिल्ली (एजेंसी)। सट्टेबाजी और जुए से संबंधित विज्ञापनों के बढ़ते मामलों से चिंतित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एक परामर्श जारी कर मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों (सेलिब्रिटीज) को इस तरह कर प्रचार गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सभी अंशधारकों को चेतावनी दी कि सट्टेबाजी और जुए सहित अवैध गतिविधियों के समर्थन के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक सरकारी बयान में कहा गया, ''सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की बढ़ते मामलों को देखते हुए सीसीपीए ने एक व्यापक सलाह जारी की है।%% उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, परामर्श में विभिन्न कानूनों के तहत निषिद्ध गैरकानूनी गतिविधियों के विज्ञापन, प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है। सीसीपीए ने कहा, ''सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ सख्ती से प्रतिबंधित है, और देशभर के अधिकांश क्षेत्रों में इसे अवैध माना जाता है। इसके बावजूद ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच और ऐप सीधे तौर पर, साथ ही गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुए का विज्ञापन करते रहते हैं। निगरानी संस्था ने बताया कि ऐसी गतिविधियों के समर्थन का विशेष रूप से युवाओं पर काफी वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है। यह सलाह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया मंचों को विभिन्न परामर्श जारी करने के प्रयासों को रेखांकित करती है, जिसमें उन्हें सट्टेबाजी और जुआ मंचों के प्रचार से आगाह किया गया है। सीसीपीए ने सभी अंशधारकों से इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने और उन गतिविधियों को बढ़ावा देने या समर्थन करने से परहेज करने को कहा, जो भारतीय कानून के तहत अवैध हैं।